रिविजनल सिविल

न्यायमूर्ति प्रेमचंद के समक्ष

गिल्लू, — याचिकाकर्ता

बनाम

दामोदर दास, ईटीसी- ***उत्तरदाता।***

1971 का सिविल संशोधन संख्या 84

5 मार्च, 1971

परिसीमा अधिनियम (1963 ***का XXXVI)*** - अनुच्छेद 47 - संपत्ति की बिक्री के लिए विचार विफल होना - इस तरह के विचार की वापसी के लिए मुकदमा - चाहे अनुच्छेद ***47 द्वारा शासित हो*** ।

यह माना गया है कि जहां बिक्री-विलेख के आधार पर संपत्ति का खरीदार संपत्ति के कब्जे में है, और बिक्री का विचार विफल हो जाता है, तो उस विचार की वापसी के लिए एक मुकदमा परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 47 द्वारा शासित होगा, और इस तरह के मुकदमे के लिए सीमा विचार की विफलता की तारीख तीन साल से अधिक है। इस तरह के मुकदमे में कार्रवाई का कारण बेदखली की तारीख पर उत्पन्न होता है, न कि बिक्री विलेख की तारीख से।

1919 के *अधिनियम* IX *की धारा* 44 *और* 115 सी.पी.ओ. *श्री एच आर गोयल, उप-न्यायाधीश, झज्जर के आदेश में संशोधन के लिए, दिनांक 7 जनवरी,* 1971, *वादपत्र के संशोधन को अस्वीकार करना।*

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एससी कपूर।

बी. एस. गुप्ता, अधिवक्ता , प्रतिवादी नंबर 1 के लिए।

निर्णय

न्यायमूर्ति प्रेम चंद पंडित —यह झज्जर के विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ वादी की पुनरीक्षण याचिका है, जिसमें वाद के संशोधन के आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

2.25 मई, 1961 को दामोदर दास ने एक पंजीकृत विलेख द्वारा, गिल्लू और उनके भाई बेदी के पक्ष में 2 बीघा, 16 बिस्वास की कृषि भूमि 3,000 रुपये में बेच दी। इस बिक्री के आधार पर 17 अगस्त, 1964 को राजस्व प्राधिकारियों द्वारा प्रतियों के पक्ष में एक नामांतरण किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में यह पता चला कि विक्रेता के पास बेची गई भूमि में केवल आधा हिस्सा था और परिणामस्वरूप, राजस्व अधिकारियों ने उत्परिवर्तन के अपने पहले के आदेश की समीक्षा की और क्षेत्र को 1 बीघा और 8 बिस्वास तक कम कर

दिया और वही 10 मई, 1966 को विक्रेताओं के पक्ष में उत्परिवर्तित हुआ था। इसके बाद अप्रैल 1968 में गिल्लू और उनके भाई ने दामोदर दास के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया, जिसमें घोषणा की गई कि वे 2 बीघा और 16 बिस्वास के मालिक थे, जिन्हें प्रतिवादी द्वारा उनके पक्ष में बेचा गया था।

3.प्रतिवादी ने कई याचिकाओं पर मुकदमा दायर किया था। हालांकि, उन्होंने बिक्री-विलेख के निष्पादन को स्वीकार किया; लेकिन दलील दी कि मुकदमा सीमा द्वारा रोक दिया गया था। प्रतिवादी द्वारा ली गई अन्य आपत्तियों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे पार्टियों के बीच वर्तमान विवाद के निर्धारण के लिए आवश्यक नहीं हैं।

4.दोनों पक्षों द्वारा साक्ष्य का नेतृत्व किया गया और केवल वादी का बयान दर्ज किया जाना बाकी था, जब 4 नवंबर, 1970 को उनके द्वारा आदेश 6, नियम 17 और वाद में संशोधन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत एक आवेदन किया गया था। वे इसमें निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ना चाहते थे -

> "यदि प्रतिवादी को बेची गई भूमि के केवल आधे हिस्से का मालिक माना जाता है, तो वादी विचार के लिए वास्तविक खरीदार के रूप में प्रतिवादी से डेढ़ शेयर और नुकसान के लिए कीमत के रूप में 3,000 रुपये का दावा करने के हकदार हैं।".

5.इस आवेदन का प्रतिवादी द्वारा विरोध किया गया था और इसे ट्रायल जज द्वारा मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि यदि वादी अब बिक्री विचार के एक हिस्से की वापसी के लिए मुकदमा लाता है, तो इसे सीमा द्वारा रोक दिया जाएगा। ट्रायल कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ वर्तमान याचिका केवल वादी गिल्लू ने दायर की है।

6.पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद, मेरा विचार है कि इस याचिका को स्वीकार किया जाना चाहिए। यह विवादित नहीं है कि वादी आज तक पूरी भूमि के कब्जे में हैं। यह भी सहमति है कि प्रतिवादी के पास भूमि में केवल आधा हिस्सा है, जिसे उसने 25 मई, 1961 को बिक्री-विलेख के माध्यम से बेचा था। यदि विचार विफल हो जाता है, तो उस विचार की वापसी के लिए एक मुकदमा परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 47 द्वारा शासित किया जाएगा, और इस तरह के मुकदमे के लिए सीमा विचार की विफलता की तारीख से तीन साल है। यह बासप्पा बनाम *कोडलियाह*, (1), *में* के. एस. हेगड़े, जे. द्वारा आयोजित किया गया है कि इस तरह के मुकदमे में कार्रवाई का कारण निपटान की तारीख पर उत्पन्न होता है, न कि बिक्री-विलेख की तारीख से। इसी तरह का दृष्टिकोण आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा *इलावज्जुला रामलिंगम और अन्य कोर्राप्रोलु वीरभद्रैया और एक अन्य* (2) *मामले* में लिया गया था, जहां यह देखा गया था कि शीर्षक के लिए वाचा के उल्लंघन के लिए क्षतिपूर्ति के मुकदमे में और चुपचाप आनंद के लिए शीर्षक के साथ-साथ शांत आनंद के लिए वाचा को उसी समय तोड़ा जा सकता है, अर्थात, जब वास्तविक या रचनात्मक कब्जा था।

7.प्रतिवादियों के विद्वान वकील द्वारा विपरीत दृष्टिकोण अपनाने वाले किसी भी अधिकारी को मेरे ध्यान में नहीं लाया गया था। ऐसा होने पर, यह माना जाता है कि वर्तमान मामले में विचार की वापसी के लिए एक मुकदमा सीमा द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। वादी किसी भी नए तथ्यों की पैरवी नहीं करना चाहते हैं। उन्हें इस वैकल्पिक राहत के माध्यम से दावा किए जाने वाले धन की राशि पर अदालत-शुल्क का भुगतान करना होगा। कार्यवाही की बहुलता से बचने के लिए, तत्काल मामले में संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए थी।

8.इसलिए, मैं आक्षेपित आदेश को रद्द करता हूं और संशोधन आवेदन की अनुमति देता हूं। हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जोगिंद्र जांगड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

हथीन, हरियाणा